**समक्ष एस.एस. सोढ़ी , माननीय न्यायमूर्ति।**

**कौशल्या देवी और अन्य – *याचिकाकर्ता***

***बनाम***

**मोहन लाल और अन्य, – प्रतिवादियों**

**1981 के आदेश क्रमांक 442 से प्रथम अपील**

**2** अप्रैल, **1984**

मोटर वाहन अधिनियम (***1939*** का चतुर्थ) - धारा ***110***-ए - उपधारा (***1)*** परंतुक - सभी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर दावा आवेदन - ऐसे प्रतिनिधियों को छोड़कर जो अन्य प्रतिनिधियों के पक्ष में अधिकारों का समर्पण करते हैं - दावा याचिका - चाहे इसके लिए बुरा हो एक आवश्यक पक्ष का नॉन-जॉइंडर-ट्रिब्यूनल-क्या दावेदार को छोड़े गए प्रतिनिधि को फंसाने का मौका देने के लिए बाध्य है।

अभिनिर्णित, कि अनुभाग की उपधारा (1) के परंतुक का वाचन मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के 110-ए से पता चलेगा कि यह लागू है, जहां मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है, वहां किया गया आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए होना चाहिए। यह भी उतनी ही अनिवार्य आवश्यकता है मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों

को पार्टियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे सह-याचिकाकर्ता हों या प्रतिवादी हों, जैसा कि उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से एक ही दुर्घटना के संबंध में विविध दावों से बचने के उद्देश्य से पेश किया गया है। यदि सभी कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को दावे के पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, वहां दावेदारों को कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें पक्षकार बनाया जाए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, दावा आवेदन में कार्यवाही जारी न रहने दी जाए।

(पैरा ***5*** और *6)*

*प्रथम अपील श्री राज कुमार गुप्ता की अदालत, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, करनाल के आदेश, दिनांक 28 मई, 1981 से हुई, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया और मामले की परिस्थितियों में पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश दिया गया।*

*आर. एम. सूरी, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के लिए।*

*उत्तरदाताओं* **2** *से* **4** *के लिए हरभगवान सिंह, ए.जी., हरियाणा, पी.एस. दुहान, डी.ए.जी., हरियाणा के साथ।*

**निर्णय**

एस.एस.सोढ़ी, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) इस अपील में विचार के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-ए की उप-धारा (1) का प्रावधान है।

(2) देश कुमार की मौत बस से हुई दुर्घटना में हो गयी थी. यह 18 अक्टूबर, 1980 को समालखा में हुआ। उनकी मृत्यु उनके पीछे उनकी मां श्रीमती कौशल्या देवी, उनके भाई जय भगवान, उनकी बहन प्रेम लता और उनकी विधवा शशि बाला को छोड़कर हो गई।

(3) *मृतक* की मां, भाई व बहन की ओर से मुआवजे के लिए दावा किया गया था. हालाँकि, विधवा को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था, जबकि प्रतिवादी द्वारा उसके गैर-जुड़ावकर्ता पर एक विशेष आपत्ति उठाई गई थी। इसके बजाय दावेदारों ने विधवा शशि बाला, प्रदर्शनी पीआई के हलफनामे को रिकॉर्ड पर रखकर इस आपत्ति को पूरा करने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि वह अपने माता-पिता के घर

गई थी और उनकी मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए अपना दावा छोड़ दिया था। उनके मृत पति ने उनकी सास श्रीमती कौशल्या देवी के पक्ष में।

(4) ट्रिब्यूनल ने माना कि हलफनामा एक्ज़िबिट पीआई कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और तदनुसार, विधवा शशि बाला के इस याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल न होने के कारण याचिका को खारिज कर दिया।

(5) इस मामले से निपटने के लिए रंगनाथन बनाम के. गंगाबाई और अन्य (1) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देना उचित होगा। इस मामले में पिता ने मोटर दुर्घटना में अपने बेटे की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए दावा दायर किया था। आपत्ति उठाई गई कि मृतक की मां के जीवित होने के कारण, पिता इस तरह का दावा करने का हकदार नहीं है। ट्रिब्यूनल ने इस आपत्ति को बरकरार रखते हुए कहा कि पिता, मां को सह-याचिकाकर्ता या प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना मुआवजे के लिए याचिका बरकरार नहीं रख सकता। इस संदर्भ में, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के प्रावधानों पर विचार करते समय, यह देखा गया- "यह धारा कहती है कि जहां दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई

है, दावा याचिका सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दायर की जा सकती है।" मृतक का. लेकिन उक्त धारा में एक प्रावधान है, जो कहता है कि जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए ऐसे किसी भी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, तो आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। जो कानूनी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा। धारा 110-ए का यह प्रावधान स्पष्ट रूप से एक ही दुर्घटना के संबंध में विविध दावों से बचने के उद्देश्य से पेश किया गया है। यदि कई कानूनी प्रतिनिधियों में से एक अन्य के संदर्भ के बिना दावा याचिका दायर कर सकता है तो एक ही दुर्घटना के संबंध में कई दावा याचिकाएं दायर होने की संभावना है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजा न मिले और वह अन्य कानूनी प्रतिनिधियों की जानकारी के बिना इसे लेकर भाग न जाए, यह प्रावधान पेश किया गया है।" तदनुसार मामले को ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया ताकि पिता को मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिवादी के रूप में रिकॉर्ड पर लाने और प्रतिनिधि क्षमता में दावा याचिका पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया जा सके।

(6) इस प्रकार, यह अनिवार्य है कि - जहां मुआवजे के लिए आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया है, किया गया आवेदन मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए होना चाहिए। यह समान रूप से एक अनिवार्य आवश्यकता है कि मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को पार्टियों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वह सह-याचिकाकर्ता हों या प्रतिवादी। यदि इन शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो याचिका आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जहां मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों को दावे के लिए पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, वहां दावेदारों को कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए, न कि इस तरह से पक्षकार बनाया जाए और जब तक कि ऐसा नहीं किया जाता है, दावा आवेदन में कार्यवाही जारी न रहने दी जाए।

(7) ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया गया है और मामले को ट्रिब्यूनल को भेज दिया गया है ताकि दावेदारों को विधवा-शशि बाला को प्रतिवादी बनाने का मौका दिया जा सके और उसके बाद कानून के अनुसार दावे पर नए सिरे से फैसला किया जा सके।

(8) यह अपील तदनुसार स्वीकार कर ली गई है - और पार्टियों को 1 मई, 1984 को ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

*अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

सचिन कुमार सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

नूँह, हरियाणा